

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बदलती गतिशीलता*

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की पूंजी आवश्यकताओं के वित्तपोषण का एक स्थिर साधन है और विकसित तथा उभरती दोनों अर्थव्यवस्थाओं ने बाजार मूल्य पर एफडीआई पर सूचना आधार को बढ़ाने के लिए बड़े प्रयास किए हैं। भारत में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के समन्वित प्रत्यक्ष निवेश सर्वेक्षण (सीडीआईएस) के कार्यान्वयन और विदेशी संबद्ध व्यापार सांख्यिकी (एफएटीएस) के संकलन द्वारा इस संबंध में प्रमुख प्रगति हुई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के विश्लेषण के अनुभवजन्य परिणाम दर्शाते हैं कि व्यापार में खुलापन, आर्थिक विकास, बाजार का आकार, श्रम लागत और मेजबान देशों का खुला पूंजी खाता, एफडीआई अंतर्वाह के प्रमुख निर्धारक हैं।

I. प्रस्तावना

विदेशी निवेश विश्व की किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बचत-निवेश के अंतर को पाटकर पूंजी घाटे वाली अर्थव्यवस्था की निवेश आवश्यकताओं को पूरा करके आर्थिक विकास का समर्थन करता है। कई विदेशी निवेशक वित्तीय पूंजी के साथ नई तकनीक, सर्वोत्तम प्रथाएं और अभिशासन अपनाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कौशल हस्तांतरण और उत्पादकता का लाभ प्राप्त होता है। हालांकि, नया व्यवसाय रोजगार का निर्माण कर सकता है, नई कंपनियों से अधिक प्रतिस्पर्धा के कारण भी मेजबान देश में दक्षता बेहतर होती है।

देश के राष्ट्रीय वित्तीय खातों में एक घटक, विदेशी निवेश, इक्विटी और ऋण के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। यह प्राप्तकर्ता अर्थव्यवस्था में निवेशक के स्थायी प्रबंधन हित से जुड़ा है और इसलिए, एक अधिक स्थिर घटक है। जबकि विदेशी पोर्टफोलियो

* यह लेख सुमित रॉय, वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, जॉली रॉय और कमल गुप्ता, सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किया गया है। इस लेख में व्यक्त विचार और राय लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे आरबीआई के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों। त्रुटियाँ, यदि कोई हों, लेखकों की हैं।

प्रवाह चालू खाता घाटे के वित्तपोषण के लिए महत्वपूर्ण हैं, कई देश सामान्य और साथ ही चुनिंदा क्षेत्रों में एफडीआई पर ध्यान और प्रोत्साहन देते हैं।

यह लेख भारत के लिए पूंजी स्टॉक के आवक एफडीआई घटक पर ध्यान केंद्रित करता है जो 1990 में यूएस \$ 1.7 बिलियन से बढ़कर 2019 में यूएस \$ 427.0 बिलियन से अधिक हो गया है। हम विश्लेषण में उपयोग के लिए निरंतर आंकड़ों की उपलब्धता, मूल्यांकन संबंधित विषयों सहित इसकी सीमाओं और भागीदार देशों द्वारा सृजित आँकड़ों की तुलना पर भी चर्चा करते हैं। लेख का शेष भाग पांच खंडों में व्यवस्थित है। खंड II स्वतंत्रता के बाद से भारत में एफडीआई नीति के विकास का सारांश प्रस्तुत करता है। वैश्विक पूंजी प्रवाह के विकास और भारत के लिए आवक एफडीआई में प्रवृत्तियों की चर्चा खंड III में की गई है। सीडीआईएस पहल, एफडीआई सूचना आधार और भारतीय डेटा पर आधारित एफडीआई निवेश के मूल्यांकन के मुद्दे पर खंड IV में चर्चा की गई है। खंड V, पैनाल प्रतिगामी विश्लेषण का उपयोग करके प्रमुख देशों को ध्यान में रखते हुए, भारत में बाजार मूल्य पर उनके एफडीआई शेयरों के संदर्भ में आवक एफडीआई को प्रभावित करने वाले कारकों का अनुभवजन्य विश्लेषण प्रस्तुत करता है। खंड VI में निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

II. भारत में एफडीआई नीति का विकास – संक्षिप्त परिचय

1948 में, जब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा भारत की अंतर्राष्ट्रीय आस्तियों और देयताओं का पहला सर्वेक्षण किया गया था, तो देश में विदेशी निवेश का स्टॉक ₹256 करोड़ था, जो बड़े पैमाने पर यूके से आ रहा था और इसका बड़ा हिस्सा प्राकृतिक संसाधनों की खोज और व्यापार से संबन्धित था। स्वतंत्रता के तुरंत बाद, भारत ने विकास योजना ढांचे में आयात के स्थान पर औद्योगीकरण की रणनीति शुरू की। मार्च-1950 तक, औद्योगीकरण की रणनीति ने मशीनरी निर्माण क्षेत्र सहित भारी उद्योगों में स्थानीय क्षमता के विकास के लिए धुरी का निर्माण किया। घरेलू प्रौद्योगिकी, कौशल, उद्यमिता के विस्तार संबंधी कठिनाइयों और 1957-58 के विदेशी मुद्रा संकट ने एफडीआई के प्रति सरकार के रवैये को और उदार बनाया। सरकार ने 1961 में उन उद्योगों की सूची जारी की जहां योजना लक्ष्यों के संबंध में

क्षमता में अंतराल को ध्यान में रखते हुए विदेशी निवेश का स्वागत किया जाना था।

देश में एफडीआई स्टॉक 1948 में ₹256 करोड़ से दोगुना से अधिक होकर 1964 में ₹566 करोड़ हो गया और मार्च 1974 में बढ़कर ₹916 करोड़ हो गया (हुड्डा, 2011)। स्थानीय लाभों के निर्माण से एफडीआई स्टॉक में विनिर्माण की हिस्सेदारी में तेजी से वृद्धि हुई जो स्वतंत्रता के समय लगभग 20 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत से अधिक हो गई और इसमें उपभोक्ता, अर्धनिर्मित और पूंजीगत वस्तुएं शामिल थीं। 40 प्रतिशत तक विदेशी निवेश या विदेशी इक्विटी के सहयोग से जुड़े सभी मामलों से निपटने के लिए विदेशी निवेश बोर्ड का गठन 1968 में किया गया था और 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी स्वामित्व वाले मामलों की जांच के लिए एक कैबिनेट समिति का गठन किया गया था।

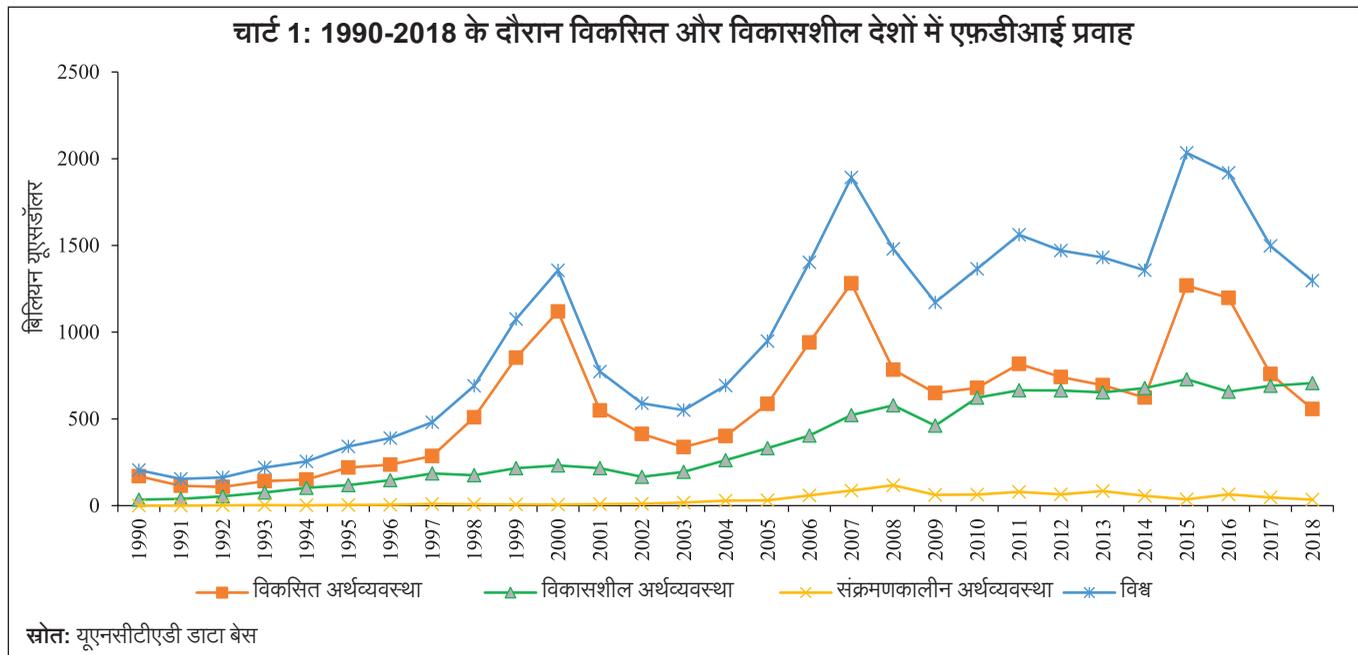
1985 तक, भारत को भुगतान संतुलन की समस्याओं का सामना करना पड़ा। 1991 में अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जमाराशियों की निकासी, बैंकों से अल्पकालिक पूंजी के बहिर्वाह और निर्यात प्रदर्शन में गिरावट जैसे अनेक मुद्दों के कारण समस्या और गंभीर हो गई। बाद के समष्टि-आर्थिक स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया और जुलाई 1991 में एक नई औद्योगिक नीति (एनआईपी) की घोषणा की गई। एनआईपी और बाद के नीतिगत संशोधनों ने देश में विशेष रूप से एफडीआई पर लागू होने वाली औद्योगिक नीति व्यवस्था को उदार बनाया। इसमें रणनीतिक या पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों में औद्योगिक अनुमोदन प्रणाली को समाप्त करना, 34 उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51 प्रतिशत एफडीआई की स्वतः स्वीकृति, अनिवार्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों को समाप्त करना, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की स्थापना आदि शामिल हैं। खनन, बैंकिंग, दूरसंचार, राजमार्ग निर्माण और प्रबंधन जैसे नए क्षेत्रों को विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों सहित निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया।

पिछले दशक के दौरान, भारत ने एफडीआई अंतर्वाह बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया और एक व्यापक एफडीआई उदारीकरण रणनीति को अपनाया। 2015 के दौरान, 15 प्रमुख क्षेत्रों में एफडीआई नियमों में ढील दी गई, जिसमें कृषि, नागरिक उड्डयन,

निर्माण, रक्षा, विनिर्माण और खनन शामिल हैं। 2016 में, स्टार्ट-अप में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने और विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों के लिए निवेश व्यवस्था को उदार बनाने के लिए प्रत्यक्ष निवेश नियमों में और संशोधन किया गया। 2019 के दौरान, एकल-ब्रांड खुदरा कारोबार, विमान सेवा और ऊर्जा वितरण में विदेशी निवेश पर प्रतिबंधों में ढील दी गई। 2020 की शुरुआत में, घरेलू ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं के हितों की रक्षा के लिए ई-कॉमर्स के लिए एफडीआई नीति को उदार बनाया गया था।

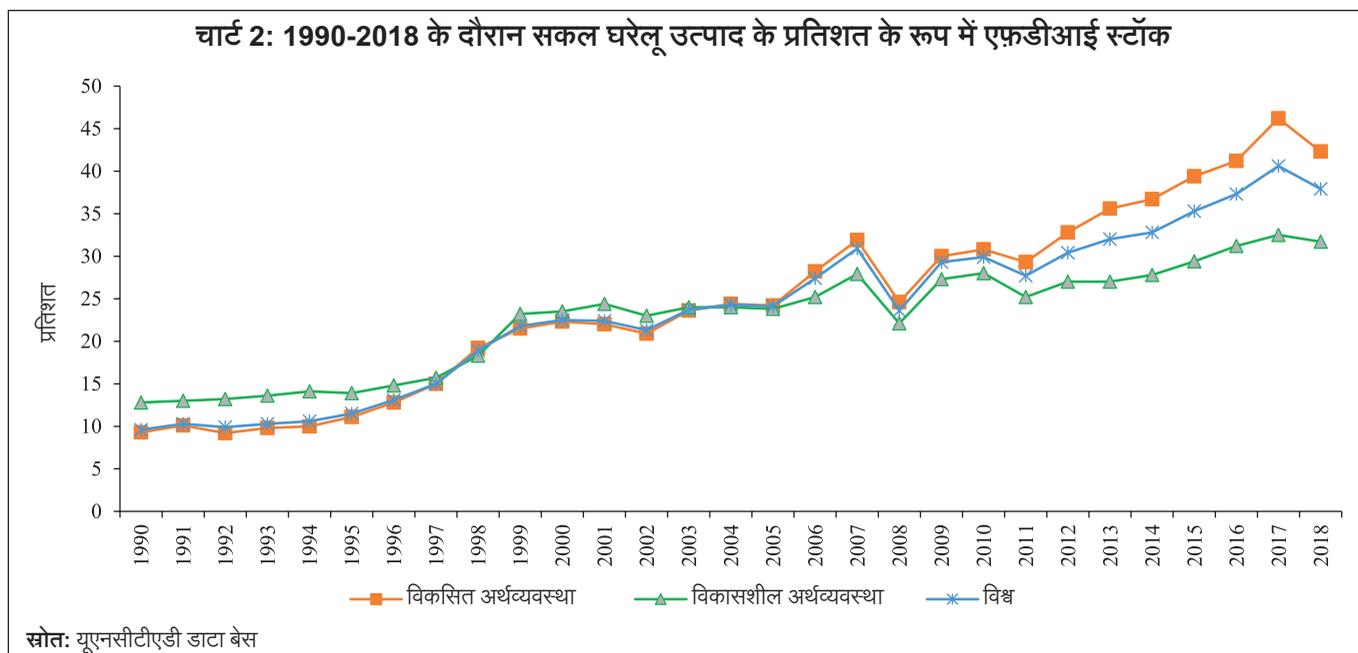
III. भारत के लिए वैश्विक पूंजी प्रवाह और आवक एफडीआई

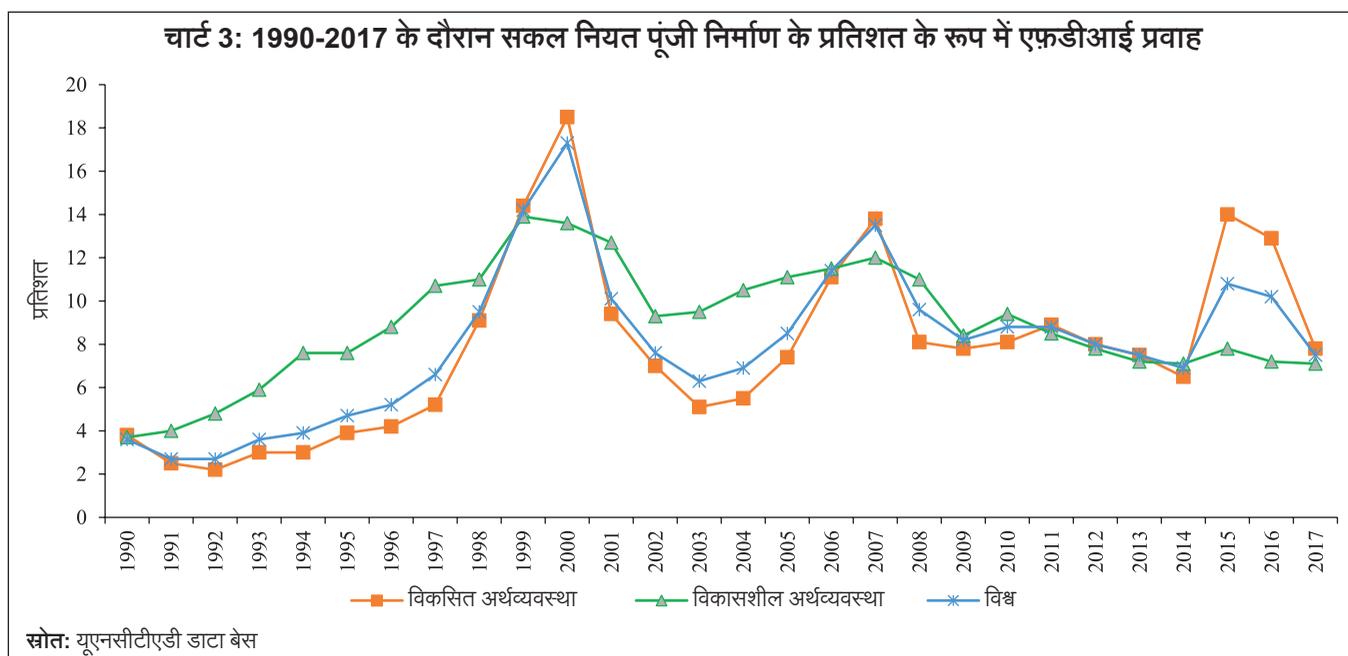
पिछले कुछ दशकों में वैश्विक व्यापार की तुलना में एफडीआई में तेजी से वृद्धि हुई है। हालांकि, विकसित अर्थव्यवस्थाएं 1990 के बाद से प्रमुख केंद्रीय बैंकों से बड़े पैमाने पर नीति समर्थन के तहत सबसे अधिक वित्तीय रूप से एकीकृत रही हैं, इस बीच अधिक विकासशील देशों ने अपनी वित्तीय प्रणालियों और प्रत्यक्ष निवेश नीतियों को उदार बनाया है। इसके परिणामस्वरूप, एफडीआई अंतर्वाह 1997 की शुरुआत से 2007-2008 के वित्तीय संकट तक तेजी से बढ़ा। 2009 के दौरान, अंतर्वाह की एक लहर देखी गई, जिसके बाद 2010 से यूरोपीय ऋण संकट बिगड़ने के कारण एफडीआई प्रवाह में एक और उछाल आया। 2014 में, सीमा-पारीय विलय और अधिग्रहण (एम एंड ए) में 432 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 721 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई, जिससे प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह का वैश्विक उछाल आया। हालांकि, 2017 से विकसित देशों और अर्थव्यवस्थाओं में एफडीआई अंतर्वाह में, मुख्य रूप से, संचित विदेशी आय पर कर देयताओं को हटाने के कारण, गिरावट जारी रही। विकासशील देशों में एफडीआई अंतर्वाह स्थिर रहा, जिससे वैश्विक एफडीआई में उनकी हिस्सेदारी 2017 में 46 प्रतिशत से बढ़कर 2018 में 54 प्रतिशत हो गई। हालांकि, 2017 के बाद से एफडीआई में मंदी के बावजूद, अमेरिका एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना रहा, इसके बाद चीन, हांगकांग और सिंगापुर का स्थान रहा। विकासशील देशों और विकसित देशों (चार्ट 1 और 2) के लिए जीडीपी के प्रतिशत के रूप में एफडीआई आवक स्टॉक पर्याप्त है। 2000-2018 की अवधि के दौरान विकासशील देशों में एफडीआई अंतर्वाह में वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप, उनका एफडीआई अंतर्वाह विकसित देशों की तुलना में अधिक रही और वैश्विक एफडीआई अंतर्वाह के आधे से अधिक हिस्से



को हासिल किया। 1990-2018 के दौरान विकासशील देशों के आवक एफडीआई शेयरों का हिस्सा उनके सकल घरेलू उत्पाद का 24.6 प्रतिशत रहा, जबकि विकसित देशों में यह 22.7 प्रतिशत था। 1990-2017 के दौरान एफडीआई अंतर्वाह ने विकासशील देशों में सकल अचल आस्ति निर्माण के लगभग 9 प्रतिशत की औसत हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व किया, जबकि

विकसित देशों में यह 8 प्रतिशत था (चार्ट 3)। 2000 से 2018 तक आवक एफडीआई अंतर्वाह द्वारा मापित विकासशील देशों और विकसित देशों में शीर्ष दस स्थान वाले देश, एफडीआई (सारणी 1 और 2) के लिए विकासशील और विकसित देशों के आकर्षण के विभिन्न आयाम को दर्शाते हैं। विकासशील देशों में, संभवतः अन्य विकासशील देशों की तुलना में सस्ते ऑनशोर





मुद्रा बाजार लिखतों के कारण, चीन एफपीआई का सबसे अधिक प्राप्तकर्ता है, दूसरी ओर, अमेरिका अपने अभिनव और टिकाऊ पूंजी बाजार के कारण एफपीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना रहा, जो दुनिया भर में पोर्टफोलियो निवेशकों को आकर्षित करता है।

20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारी वृद्धि के साथ ही सरकार के नीतिगत रुख में भी उल्लेखनीय बदलाव आया। 1991 में, देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माहौल को उदार बनाने और मजबूत करने के लिए

नीतिगत उपायों की एक श्रृंखला की घोषणा की गई थी। परिणामस्वरूप, भारत में एफडीआई अंतर्वाह 1998-99 में 2.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2008 में संकट से ठीक पहले 26.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया। वैश्विक वित्तीय संकट (2008) ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि और दुनिया भर में एफडीआई अंतर्वाह को प्रभावित किया और भारत इससे अछूता नहीं रहा। भारत में एफडीआई अंतर्वाह 2013-14 तक कम रहा। 2013 में, सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर 4 प्रतिशत तक धीमी हो गई, और चालू खाता घाटा सकल घरेलू

सारणी 1: शीर्ष 10 एफडीआई - 2018 में विकासशील देशों की स्रोत अर्थव्यवस्थाएं और 2018 में एफपीआई प्रवाह

अर्थव्यवस्था	(बिलियन यूएस डॉलर और जीडीपी का प्रतिशत)				बिलियन यूएस \$	
	एफडीआई अंतर्वाह		जीडीपी का प्रतिशत		पोर्टफोलियो प्रवाह	
	2018	औसत वृद्धि (प्रतिशत) 2000-18	2018	सकल घरेलू उत्पाद में औसत हिस्सा (प्रतिशत) 2000-18	2018	औसत वृद्धि (प्रतिशत) 2000-18
चीन	139.0	10.6	1.7	3.2	60.7	1.2
चीन, हांगकांग एसएआर	115.7	48.4	26.8	29.4	-2.4	0.3
सिंगापुर	77.6	42.6	24.4	19.3	-3.7	-0.5
ब्राज़िल	61.2	25.1	4.1	3.3	-3.1	-0.2
केमैन टापू	57.4	26.4	N.A	N.A	N.A	N.A
ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड्स	44.2	11.1	N.A	N.A	N.A	N.A
भारत	42.3	35.7	1.6	1.6	-4.4	-0.2
मेक्सिको	31.6	11.8	3.2	2.8	2.4	-0.4
इंडोनेशिया	22.0	13.0	1.8	1.2	-3.7	-1.4
वियतनाम	15.5	24.7	6.3	5.5	N.A	N.A

स्रोत: अंकटाड डेटा बेस से एफडीआई अंतर्वाह; विश्व विकास संकेतक से पोर्टफोलियो अंतर्वाह और ओईसीडी से जीडीपी के प्रतिशत के रूप में एफडीआई अंतर्वाह।

सारणी 2: शीर्ष 10 एफडीआई - 2018 में विकसित देशों की स्रोत अर्थव्यवस्थाएं और 2018 में एफपीआई

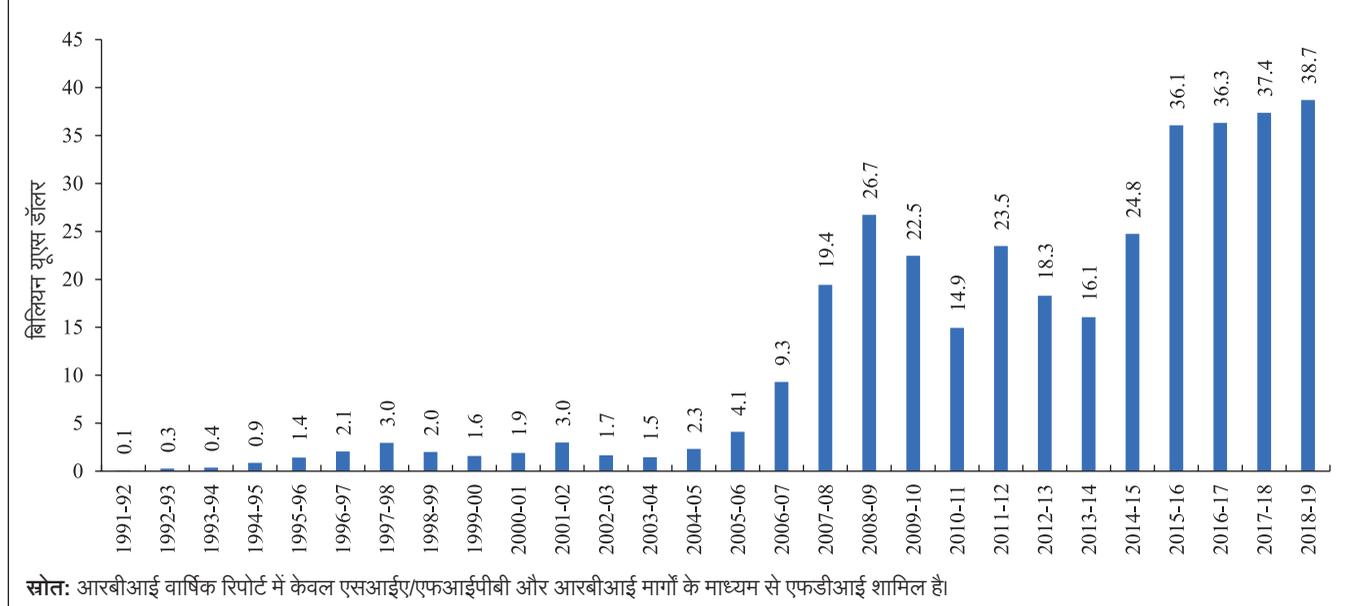
अर्थव्यवस्था	(बिलियन यूएस डॉलर और सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)				बिलियन यूएस \$	
	एफडीआई अंतर्वाह		जीडीपी का प्रतिशत		पोर्टफोलियो प्रवाह	
	2018	औसत वृद्धि (प्रतिशत) 2000-18	2018	सकल घरेलू उत्पाद में औसत हिस्सा (प्रतिशत) 2000-18	2018	औसत वृद्धि (प्रतिशत) 2000-18
संयुक्त राज्य अमरीका	251.8	14.2	1.3	1.8	142.4	0.7
नीदरलैंड	69.7	-7.0	7.2	25.2	-54.0	-0.3
यूनाइटेड किंगडम	64.5	25.8	2.8	4.6	5.6	0.5
ऑस्ट्रेलिया	60.4	78.6	4.3	3.5	-7.1	0.1
स्पेन	43.6	39.3	3.5	3.2	-15.6	0.6
कनाडा	39.6	6.2	2.7	3.3	20.1	-0.2
फ्रांस	60.4	-18.0	2.1	2.1	-20.7	0.4
जर्मनी	37.3	-11.5	4.3	2.1	-42.0	-0.6
इटली	25.7	-20.5	1.9	1.2	-5.4	-0.5
इजराइल	24.3	28.7	5.6	3.8	-8.3	-2.0

स्रोत: अंकटाड डेटा बेस से एफडीआई अंतर्वाह; विश्व विकास संकेतक से पोर्टफोलियो अंतर्वाह और ओईसीडी से जीडीपी के प्रतिशत के रूप में एफडीआई अंतर्वाह।

उत्पाद के लगभग 5 प्रतिशत के अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया। इन व्यापक आर्थिक अनिश्चितताओं ने भारत में निवेश करने के लिए विदेशी निवेशकों की चिंता को बढ़ा दिया। उच्च मुद्रास्फीति और अन्य व्यापक आर्थिक समस्याओं के बीच, 2012-13 की तुलना में 2013-14 में, भारत में एफडीआई अंतर्वाह में गिरावट देखी गई। सितंबर 2014 के दौरान, भारत सरकार ने निवेश की सुविधा, नवाचार को बढ़ावा देने और सर्वोत्तम निर्माण के लिए

‘मेक इन इंडिया’ पहल शुरू की। उक्त सुधार ने भारत में एक सकारात्मक विदेशी निवेश माहौल का निर्माण किया और मुख्य रूप से शीर्ष तीन उद्योग प्राप्तकर्ताओं जैसे ‘विनिर्माण’, ‘संचार’ और ‘वित्तीय सेवाओं’ में मजबूत निवेश के कारण एफडीआई अंतर्वाह में वृद्धि में मदद की। भारत में एफडीआई अंतर्वाह 2014-15 से 2018-19 के दौरान बढ़ती प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है (चार्ट 4)।

चार्ट 4: 1991-92 से 2018-19 तक भारत में एफडीआई अंतर्वाह



सारणी 3: भारत में संचयी एफडीआई प्रवाह में हिस्सेदारी (2015-2019)

देश	संचयी अंतर्वाह (%)
सिंगापुर	27.7
मॉरीशस	27.0
अमेरीका	7.5
नीदरलैंड	7.5
जापान	7.0
कुल	76.7

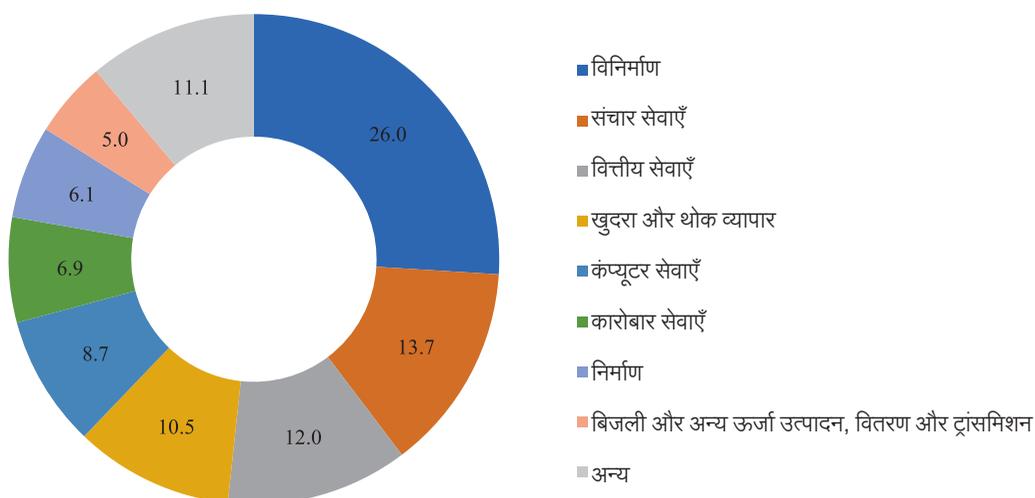
स्रोत: आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट (2018-19) में केवल एसआईए/एफआईपीबी और आरबीआई मार्गों के माध्यम से एफडीआई शामिल है।

2015 से 2019 के दौरान, भारत को 173.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संचयी एफडीआई अंतर्वाह प्राप्त हुआ और भारत में शीर्ष पांच निवेश करने वाले देशों की हिस्सेदारी 76.7 प्रतिशत रही। सिंगापुर और मॉरीशस ने मिलकर भारत में कुल विदेशी निवेश का आधे से अधिक हिस्सा हासिल किया, जिसमें कुल संचयी एफडीआई अंतर्वाह में 27.7 प्रतिशत का उच्चतम हिस्सा सिंगापुर का था (सारणी 3)। 2015-2019 के दौरान तीन प्रमुख क्षेत्रों अर्थात 'विनिर्माण क्षेत्र', 'संचार सेवा' और 'वित्तीय सेवा' ने समग्र रूप से 89.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एफडीआई अंतर्वाह में 50 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी प्राप्त की (चार्ट 5)।

IV. एफडीआई सूचना आधार और सीडीआईएस

भारत की विदेशी देयताओं और आस्तियों (FLA) की पहली जनगणना 1948 में की गई थी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक अधिनियम, 1944 के तहत जानकारी एकत्र की गई थी। बाद की अवधि में आंकड़े अलग-अलग समय-अंतराल पर संकलित किये गए थे। 1997 से, रिपोर्टिंग वार्षिक थी, लेकिन 2010 तक भागीदारी अनिवार्य नहीं थी। 2010-11 से, उन भारतीय कंपनियों के लिए रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी गई, जिन्होंने एफडीआई प्राप्त किया है और/या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) किया है। इसने भारत को 2010 के बाद से आईएमएफ के सीडीआईएस में भाग लेने में सक्षम बनाया। आईएमएफ द्वारा वार्षिक आधार पर प्रकाशित प्रत्यक्ष निवेश करने वाले देशों के आधार पर वर्गीकृत बाजार मूल्यों पर भारत के सीडीआईएस आंकड़े (आवक और जावक प्रत्यक्ष निवेश दोनों) अब शोधकर्ताओं और विश्लेषकों के उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। एफडीआई कंपनियों ने 2012-13 से रिजर्व बैंक की वार्षिक एफएलए जनगणना के हिस्से के रूप में एफडीआई और/या ओडीआई डेटा पर विस्तृत डेटा प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है। विदेशी संबद्ध व्यापार सांख्यिकी (एफएटीएस) अर्थात निर्यात, आयात, घरेलू बिक्री और विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियों की खरीद की जानकारी भी एक साथ एकत्र की जाती है।

चार्ट 5: 2015-19 के दौरान क्षेत्रवार संचयी एफडीआई अंतर्वाह (प्रतिशत में)



स्रोत: आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट में केवल एसआईए/एफआईपीबी और आरबीआई मार्गों के माध्यम से एफडीआई शामिल है।

भारतीय प्रत्यक्ष निवेश कंपनियों (2018-19) की एफएलए पर जनगणना से पता चलता है कि कुल एफडीआई स्टॉक का लगभग 95 प्रतिशत (मार्च 2019 में बाजार मूल्य पर 32,92,902 करोड़ रुपये) इक्विटी में था। समग्र स्तर पर, रेस्पोंडिंग कंपनियों के अंकित मूल्य पर कुल इक्विटी में एफडीआई हिस्सेदारी 81 प्रतिशत से अधिक थी; क्योंकि प्रत्यक्ष निवेश की सूचना देने वाली कंपनियों में से लगभग तीन-चौथाई कंपनियां विदेशी कंपनियों की भारतीय सहायक कंपनियां थीं। बढ़ते वैश्वीकरण के साथ, भारतीय कंपनियां अधिक बहिर्गामी हो रही हैं और स्थायी हित के साथ विदेशी निवेश कर रही हैं। मार्च 2018 और 2019 दोनों में भारत के प्रत्यक्ष अंतर्वाही निवेश का अनुपात लगभग 18 प्रतिशत होने का अनुमान है। अंतर्वाही प्रत्यक्ष निवेश की सूचना देने वाली कंपनियों में से 96 प्रतिशत से अधिक गैर-सूचीबद्ध थीं और उन्होंने आईएमएफ द्वारा निर्धारित इक्विटी निवेश की स्व-निधि खाता मूल्य (ओएफबीवी) पद्धति का उपयोग करते हुए कंपनी के निवल मूल्य में निवासी इक्विटी होल्डिंग के हिस्से का अनुमान लगाया था।

एफएलए डेटाबेस में अंकित मूल्य के साथ-साथ बाजार मूल्य दोनों पर इक्विटी के स्टॉक को दर्शाया जाता है। मार्च 2019 के अंत तक, एफडीआई कंपनियों की कुल एफडीआई इक्विटी हिस्सेदारी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी अंकित मूल्य पर 46.2 प्रतिशत और बाजार मूल्य पर 53.3 प्रतिशत रही जो बाजार मूल्य के अनुपात में विभिन्न क्षेत्रों के इक्विटी के अंकित मूल्य के अनुपात में अंतर के कारण थी। (सारणी 4)।

मार्च 2019 में समग्र स्तर पर एफडीआई कंपनियों की इक्विटी के बाजार मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 5.1 था, लेकिन यह विभिन्न क्षेत्रों में 2.1 से 11.9 तक था। इसका कारण कॉरपोरेट लाभप्रदता, मध्यावधि की वृद्धि और संभावित वृद्धि सहित कई कारक हो सकते हैं। अंकित मूल्य और बाजार मूल्यांकन के बीच 0.9 का उच्च सहसंबंध बताता है कि विभिन्न क्षेत्रों के इक्विटी पर इन कारकों का प्रभाव है (सारणी 5)।

एफएलए जनगणना 2018-19 के अनुसार, अंतर्वाही एफडीआई की रिपोर्टिंग करने वाली कंपनियों में से लगभग 75 प्रतिशत एफडीआई सहायक कंपनियां ऐसी थीं, जिन्होंने अंतर्वाही एफएटी आंकड़ों की गतिविधि के अनुसार रिपोर्ट की है। एफडीआई

सारणी 4: एफडीआई कंपनियों की क्षेत्रवार इक्विटी भागीदारी: मार्च 2019

(₹ करोड़)

गतिविधि	कुल इक्विटी (निवासी और अनिवासी सहित)	एफडीआई इक्विटी हिस्सेदारी	
		अंकित मूल्य पर	बाजार मूल्य पर
1. कृषि से संबंधित, वृक्षारोपण और संबद्ध गतिविधियां	1,838	1,698	7,060
2. खनन	1,657	1,390	6,456
3. निर्माण	3,21,314	2,81,560	16,64,304
4. बिजली, गैस, भाप और एयर कंडीशनिंग आपूर्ति	47,545	27,136	59,016
5. जल आपूर्ति; सीवरेज, अपशिष्ट प्रबंधन और उपचारात्मक गतिविधियां	1,996	1,792	2,745
6. निर्माण	25,160	19,647	41,009
7. सूचना और संचार	58,874	45,448	5,41,385
8. अन्य सेवाएं	2,92,143	2,30,651	799,410
कुल	7,50,527	6,09,322	31,21,385

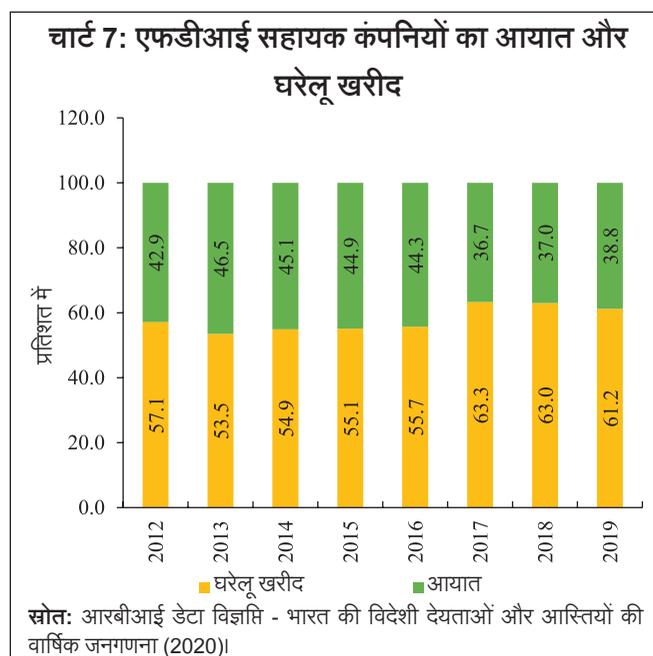
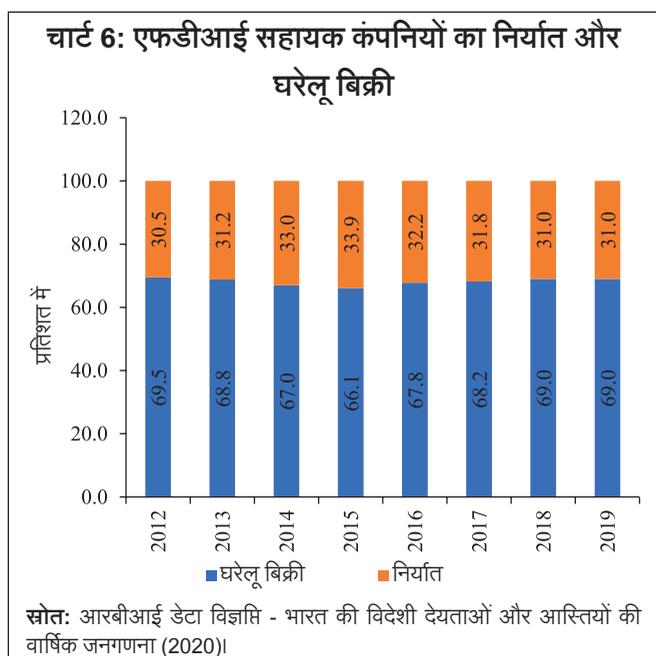
स्रोत: आरबीआई डेटा विज्ञप्ति - भारत की विदेशी देयताओं और आस्तियों की वार्षिक जनगणना (2020)।

सहायक कंपनियों के कारोबार का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से घरेलू बाजार में केंद्रित है। कुल बिक्री में एफडीआई सहायक कंपनियों के निर्यात की हिस्सेदारी 2012-2019 के दौरान औसतन 31.8 प्रतिशत रही (चार्ट 6)। 2018-19 के दौरान 'सूचना और संचार सेवाएं' प्रमुख निर्यात उन्मुख क्षेत्र रहा। विदेशी सहायक कंपनियां कच्चे माल, पुर्जों आदि की खरीद के लिए बड़े पैमाने पर भारतीय घरेलू बाजार पर निर्भर हैं (सारणी 6 और चार्ट 7)।

सारणी 5: इक्विटी अनुपात (अंकित मूल्य से बाजार मूल्य), सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि: क्षेत्र-वार

	बाजार मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात	औसत वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि (2000-19)
1. कृषि से संबंधित, वृक्षारोपण और संबद्ध गतिविधियां	4.2	3.2
2. खनन	4.6	4.2
3. निर्माण	5.9	7.5
4. बिजली, गैस और पानी की आपूर्ति	3.7	6.6
5. निर्माण	2.1	6.6
6. सूचना और संचार	11.9	18.3
7. अन्य सेवाएं	3.5	8.3
कुल	5.1	7.0

स्रोत: आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति (2020) और सीएसओ डेटा।



सीडीआईएस, आईएमएफ के नेतृत्व में सीमा पार निवेश में सूचना अंतराल को पाटने के लिए एक विश्वव्यापी सांख्यिकीय आंकड़ा संग्रहण के लिए एक प्रयास है। इसे समग्र रूप से और तत्काल समकक्ष अर्थव्यवस्था के आधार पर एफडीआई आंकड़े की उपलब्धता और गुणवत्ता दोनों में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सीडीआईएस में, कोई देश अपनी इच्छा से अपने

कैलेंडर-वर्ष के अंत में प्रत्यक्ष निवेश की स्थिति को तत्काल प्रतिपक्षों के आधार पर बाजार मूल्य पर इक्विटी और ऋण के बीच विभाजित करके रिपोर्ट करता है। बकाया विदेशी देयताओं और आस्तियों के बाजार मूल्यांकन में परिवर्तन किसी एक वर्ष के दौरान भुगतान संतुलन (बीओपी) प्रवाह से भिन्न होते हैं, क्योंकि बकाया विदेशी देयताओं और आस्तियों में मूल्यांकन परिवर्तन भी शामिल होते हैं।

सारणी 6: बाजार मूल्य और कुल निर्यात पर कुल एफडीआई का गतिविधिवार हिस्सा: 2018-19

क्र. सं.	गतिविधि	बाजार मूल्य पर कुल एफडीआई का हिस्सा (प्रतिशत)	कुल निर्यात का हिस्सा (प्रतिशत)
1	सूचना और संचार	16.7	45.5
2	वित्तीय और बीमा गतिविधियाँ	14.0	1.4
3	मोटर वाहन, ट्रैलर और अर्ध-ट्रैलर	6.9	7.2
4	अन्य सेवा गतिविधियाँ	5.2	10.7
5	खाद्य उत्पाद	4.7	0.8
6	रसायन और रासायनिक उत्पाद	4.0	1.6
7	मशीनरी और उपकरण एनईसी	3.6	3.4
8	फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय और रासायनिक उत्पाद	3.5	3.0
9	थोक और खुदरा व्यापार; मोटर वाहनों और मोटरसाइकिलों की मरम्मत	3.2	7.6
10	अन्य	38.2	18.8
कुल		100.0	100.0

स्रोत: आरबीआई डेटा विज्ञप्ति - भारत की विदेशी देयताओं और आस्तियों की वार्षिक जनगणना (2020)।

चूंकि सीडीआईएस में भाग लेने वाले सभी देश भागीदार देश-वार प्रत्यक्ष निवेश (अंतर्वाही या बहिर्गामी या दोनों) की रिपोर्ट करते हैं, इसलिए शीर्ष नौ स्रोत देशों से, जो मार्च 2019 में एफएलए जनगणना परिणामों के अनुसार भारत में समग्र रूप से एफडीआई स्टॉक का 78.9 प्रतिशत हिस्सा है, अंतर्वाही प्रत्यक्ष निवेश की स्टॉक स्थिति को सत्यापित करने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। मार्च 2019 में कुल एफडीआई स्टॉक में यूएसए की सबसे बड़ी हिस्सेदारी (17.8 प्रतिशत) थी (सारणी 7)। यह उल्लेखनीय है कि निवेश और निवेशित देशों द्वारा रिपोर्ट किए गए एफडीआई का स्टॉक विभिन्न कारणों से कई मामलों में भिन्न होता है और इसे केवल संदर्भ तिथि में केवल 3 महीने के अंतर के लिए जोड़ा नहीं जा सकता है। यह अंतर शामिल किए गए निवेशक/निवेशित फर्मों के आकलन पद्धति (जनगणना बनाम सर्वेक्षण), लेखांकन और मूल्यांकन की कठिनाइयों, रिपोर्टिंग त्रुटियों आदि के कारण भी हो सकता है।

सारणी 7: बाजार मूल्य पर स्रोत देश-वार एफडीआई

देश	भारत में एफडीआई (₹ करोड़)	
	एफएलए जनगणना परिणामों के अनुसार (मार्च '19)	सीडीआईएस में भागीदार देश द्वारा रिपोर्ट किया गया (दिसंबर '18)
अमेरीका	5,84,978	3,20,933
यूनाइटेड किंगडम	5,17,369	1,28,814
मॉरीशस	5,09,914	8,79,038
जापान	2,82,724	1,69,877
नीदरलैंड	2,50,491	1,76,888
जर्मनी	1,63,773	1,95,789
स्विट्जरलैंड	1,59,576	44,273
कोरिया गणराज्य	79,578	42,646
फ्रांस	48,135	44,199
उपरोक्त सभी देश	25,96,538	20,02,456
सिंगापुर	4,13,174	Not Reported
अन्य देश	2,83,190	All Not Reported
सभी देश	32,92,902	All Not Reported

स्रोत: आरबीआई डेटा रिलीज (2020) और आईएमएफ की वेबसाइट <http://cdiis.imf.org>

V. एफडीआई अंतर्वाह को प्रभावित करने वाले कारकों का अनुभवजन्य विश्लेषण

इस खंड में, हम प्रमुख साझेदार देशों में एफडीआई अंतर्वाह को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को निर्धारित करने के लिए भारत में एफडीआई स्टॉक का पर्याप्त हिस्सा रखने वाले एक पैनल के अभ्यास के परिणाम को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस आंकड़ा समूह में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं जैसे यूएसए, यूके, मॉरीशस, जापान, नीदरलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, कोरिया गणराज्य, फ्रांस और भारत के लिए 2009-10 से 2017-18 की अवधि के अवलोकन शामिल हैं। संपूर्ण आंकड़ा समूह विश्व बैंक, आईएमएफ, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) तथा विश्व बैंक डेटाबेस द्वारा प्रकाशित वैश्विक विकास वित्त से प्राप्त किया गया है।

एफडीआई प्रवाह को जीडीपी अनुपात में एफडीआई अंतर्वाह के रूप में मापा गया है और व्याख्यात्मक चर की सीमा रेंज में अवरोहित किया गया है। साहित्य समीक्षा के आधार पर एफडीआई प्रवाह को प्रभावित करने वाले कुछ चर ये हैं: बाजार का आकार (पीपीपी), व्यापार का खुलापन (ओपन), विनिमय दर (ईआर), श्रम भागीदारी दर (एलएबीओआर), सकल घरेलू उत्पाद के लिए कर राजस्व (टैक्स_जीडीपी), समष्टि-आर्थिक स्थिरता (जीएफडी_जीडीपी) और चयनित देशों का पूंजी खाता खुलापन सूचकांक (केए_ओपन)। क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के संदर्भ में बाजार के आकार को जीडीपी अर्थात् क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के आधार

पर प्रति व्यक्ति जीडीपी के रूप में परिभाषित किया गया है। व्यापार के खुलेपन को वर्तमान प्राप्ति और सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के भुगतान के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी देश में कम श्रम लागत और कर की दरों का एफडीआई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है (बरातकर, 2013)। यहां जिस चार पर विचार किया गया है, वह श्रम बल की भागीदारी की दर है, जिसे 15-64 आयु वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के रूप में वर्णित किया गया है, जो एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए श्रम की आपूर्ति में आर्थिक रूप से सक्रिय है। एफडीआई भी काफी हद तक विनिमय दर के उतार-चढ़ाव और मेजबान अर्थव्यवस्था की जीडीपी विकास दर पर निर्भर करेगा (सेविस और कैमुरान, 2007)। तदनुसार, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि (जीडीपी_विकास) को भी स्वतंत्र चर माना गया है। प्राप्त परिणाम दर्शाते हैं कि एफडीआई पर वित्तीय खुलेपन (पूंजी नियंत्रण को आसान बनाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है) का प्रभाव वित्तीय बाजार के विकास की तुलना में कहीं अधिक प्रत्यक्ष है। वित्तीय खुलेपन में सुधार से मेजबान देश में एफडीआई में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। चिन और इतो (2006) में प्रस्तुत किए गए किसी देश की पूंजी खाते के खुलेपन के स्तर को मापने के लिए लाया गया चिन-इटो सूचकांक को एक स्वतंत्र चर के रूप में माना गया है। इंडेक्स (केए_ओपन) का निर्माण कई ऐसे बाइनरी छद्म चर के आधार पर किया गया है, जो आईएमएफ की विनिमय व्यवस्था और विनिमय पंजीकरण (एआरईईआर) की वार्षिक रिपोर्ट में रिपोर्ट किए गए सीमा पार वित्तीय लेनदेन पर प्रतिबंधों के सारणीकरण को निर्धारित करता है। इस सूचकांक के उच्च मान का अर्थ है कि देश सीमा पार पूंजी लेनदेन के लिए उतना ही अधिक खुला है। केए_ओपन इंडेक्स '1' का मान दर्शाता है कि देश सीमा पार वित्तीय लेनदेन पर पूरी तरह से खुला है और उच्च एफडीआई प्रवाह की उम्मीद है। केंद्र सरकार के वित्त और जीडीपी अनुपात के सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) के माध्यम से प्राप्त राजकोषीय स्थिरता को भी व्याख्यात्मक चर में से एक के रूप में लिया गया है। उक्त अध्ययन में पैनल निर्धारित प्रभाव¹ प्रतिगमन मॉडल पर विचार किया और समीकरण इस प्रकार है :

¹ निर्धारित-प्रभाव (एफई) मॉडल का उपयोग स्वतंत्र चर के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। एफई एक देश के भीतर अनुमानकर्ता और परिणाम चर के बीच संबंधों की पड़ताल करता है। यह माना जाता है कि एफई उन समय-अपरिवर्तनीय विशेषताओं के प्रभाव को हटा देता है, इसलिए हम परिणाम चर पर भविष्यवाणियों के निवल प्रभाव का आकलन कर सकते हैं।

$$Y_{it} = \beta_1 X_{it} + \alpha_i + u_{it}$$

जहाँ $i = 1, 2, \dots, n$ और $t = 1, 2, \dots, T$

α_i 's व्यक्तिगत अज्ञात अवरोधन हैं

Y_{it} निर्भर चर (DV) है जहाँ $i =$ देश और $t =$ समय.

X_{it} स्वतंत्र चर के वेक्टर का प्रतिनिधित्व करता है।

β_1 गुणांक है

u_{it} एरर टर्म है

हॉसमैन परीक्षण से पता चलता है कि पैनल निर्धारित प्रभाव मॉडल उपयुक्त होगा और 2010 से 2018 की अवधि के लिए पैनल निर्धारित प्रभाव प्रतिगमन समीकरण 10 देशों (एन = 10) और 9 वर्षों (टी = 9) के लिए अनुमानित था।

अपेक्षाओं के अनुसार, पुल कारकों (चर) के गुणांक जैसे व्यापार खुलापन, विकास दर, श्रम भागीदारी दर और पूंजी खाता खुलेपन का सूचकांक (केए_ओपन) सकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण पाया गया। इसी तरह, यह पाया गया कि पीपीपी के संदर्भ में मेजबान देशों के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर प्राप्त बाजार का आकार भी एफडीआई प्रवाह को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। हालांकि, विनिमय दर, जीडीपी से जीएफडी अनुपात (जो राजकोषीय स्थिरता को दर्शाता है) और कर से जीडीपी अनुपात को सांख्यिकीय रूप से महत्वहीन पाया गया, जबकि उनके संकेत पूर्व अपेक्षाओं के अनुसार थे। पैनल के परिणाम से पता चलता है कि उच्च स्तर का खुलापन, अर्थव्यवस्था का विकास, बड़ा

बाजार आकार, पर्याप्त श्रम भागीदारी प्रमुख कारक हैं जो मेजबान देश में एफडीआई प्रवाह को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा, देश के पूंजी खाते के खुलेपन का उच्च स्तर भी अधिक एफडीआई प्रवाह को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है (सारणी 8)।

VI. निष्कर्ष

इस अवधि के दौरान, भारत के लिए एफडीआई सांख्यिकी पर कई सूचना आधार उपलब्ध हो गए हैं। विभिन्न देशों द्वारा आँकड़ों को संकलित करने में नियोजित वैश्विक अवधारणाएँ, सांख्यिकीय पद्धतियों को समझने में मदद करती हैं और परिणामी आँकड़ों का उपयोग विभिन्न देशों के बीच तुलना के लिए किया जा सकता है। बेशक, उदार निवेश योजना वाले देशों को विदेशी निवेश के आकलन में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत की एफएलए जनगणना, जो वैश्विक सीडीआईएस पहल का एक हिस्सा है, इस संबंध में एक बड़ा कदम है क्योंकि यह पूर्ण गणना के आधार पर भारत में एफडीआई के अंकित मूल्य के साथ-साथ बाजार मूल्य पर लगातार वार्षिक डेटा देता है।

एफएलए जनगणना के अनुसार और प्रमुख एफडीआई स्रोत देशों के लिए सीडीआईएस में भागीदार देश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष निवेश अनुमानों में अंतर संदर्भ तिथि, निवेशक/निवेशित फर्मों के कवरेज, आकलन पद्धति (जनगणना/सर्वेक्षण), लेखांकन और मूल्यांकन संबंधी कठिनाइयों में अंतर के कारण होता है। आईएमएफ, विश्व बैंक, ओईसीडी, यूएनसीटीएडी, यूरोपीय आयोग आदि जैसे वैश्विक सांख्यिकीय संगठन सीमा पार के आँकड़ों में ऐसी सांख्यिकीय विसंगतियों को दूर करने के लिए अवधारणाओं और विधियों के मानकीकरण किये जाने में शामिल हैं।

वैश्विक स्तर पर और क्षेत्रों/देशों में एफडीआई प्रवाह में हाल के रुझानों के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत ने आम तौर पर उच्च एफडीआई प्रवाह रहा है और अपने मजबूत घरेलू आर्थिक प्रदर्शन और सतर्क पूंजी खाता उदारीकरण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में एफडीआई नीति का क्रमिक उदारीकरण के कारण अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए शीर्ष आकर्षक स्थानों में से एक बना हुआ है।

सारणी 8: पैनल निश्चित प्रभाव अनुमान के परिणाम

चर	गुणक	कक्षा त्रुटि	टी आँकड़ा	समस्या
सी*	154.505	42.762	3.613	0.0007
पीपीपी**	0.002	0.001	2.182	0.0336
ओपन *	0.935	0.246	3.798	0.0004
जीडीपी वृद्धि**	2.950	1.380	2.137	0.0373
श्रम*	2.816	0.956	2.946	0.0030
केए -ओपन *	3.613	1.084	3.334	0.0022
ईआर	-0.058	0.051	-1.145	0.2575
जीएफडी_जीडीपी	-0.728	1.046	-0.696	0.4893
टैक्स_जीडीपी	-0.247	0.767	-0.321	0.7491

आर² = 0.87 एड आर² = 0.82

डीडब्ल्यू स्टेटा = 1.7

* 1% के स्तर पर महत्वपूर्ण ** 5% के स्तर पर महत्वपूर्ण।

विदेशी सहायक कंपनियों के लिए निवेश और संबंधित प्रदर्शन (एफएटी आंकड़े) के क्षेत्र-वार वितरण के दिलचस्प पहलुओं को संक्षेप में एफएलए जनगणना परिणामों के विश्लेषण द्वारा प्रस्तुत किया। विदेशी सहायक कंपनियों के लिए जहां खरीद में आयात की तीव्रता, बिक्री में निर्यात से अधिक रही, उनके व्यापार में विदेशी व्यापार एक बड़ा हिस्सा था।

भारत में एफडीआई स्टॉक की स्थिति के संदर्भ में प्रमुख देशों पर विचार करते हुए, आवक एफडीआई को प्रभावित करने वाले कारकों का एक अनुभवजन्य विश्लेषण दर्शाता है कि आवक एफडीआई व्यापार के खुलेपन, आर्थिक विकास की संभावनाओं, बाजार के आकार, श्रम लागत और मेजबान देशों के पूंजी खाते के खुलेपन से काफी प्रभावित है।

References

1. Cevis, I., and Camuran, B. (2007), "The economic determinants of Foreign Direct Investment in developing countries and transition economies", *The Pakistan Development Review*, 46(3):285–299.
2. Chinn, Menzie D. and Hiro Ito (2006), "What Matters for Financial Development? Capital Controls, Institutions, and Interactions", *Journal of Development Economics*, Volume 81, Issue 1, Pages 163-192 (October).
3. Division of International Trade and Finance of the Department of Economic and Policy Research, Reserve Bank of India (2010-11), "Foreign Direct Investment Flows to India", https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Content/PDFs/FDIST_110412.pdf.
4. Department for Promotion of Industry and Internal Trade, GoI, Press Note No. 1(2020 Series), "Review of Foreign Direct Investment (FDI) policy in Insurance Sector".
5. Department for Promotion of Industry and Internal Trade, GoI, Press Note No. 2(2020 Series) "Review of Foreign Direct Investment (FDI) policy on Civil Aviation: Review of Foreign Direct Investment (FDI) policy for curbing opportunistic takeovers/acquisitions of Indian companies due to the current COVID-19 pandemic".
6. International Monetary Fund (2008), "Balance of Payments and International Investment Position Manual", Sixth Edition (BPM6).
7. International Monetary Fund (1992), "Report on the Measurement of International Capital Flows", <https://www.elibrary.imf.org/view/books/071/05673-9781557753076-en/05673-9781557753076-en-book.xml>.
8. Ms. Sapna Hooda (2011), "A Study of FDI and Indian Economy, National Institute of Technology", Kurukshetra, Deemed University, Kurukshetra, Haryana, India, https://nitkr.ac.in/nit_kuk/docs/Sapna_Hooda_Thesis_A_Study_of_FDI_and_Indian_Economy.pdf.
9. Nihal Bayraktar (2013), "Foreign Direct investment and Investment Climate", Pennsylvania State University-Harrisburg, USA.
10. Press Note No. 4(2019 Series), "Review of Foreign Direct Investment (FDI) policy on various sector".
11. Reserve Bank of India, "Annual Census of India's Foreign Liabilities and Assets", RBI Bulletin, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Bulletin/PDFs/2AR_BUL10022014.pdf and https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Bulletin/PDFs/02AR_10041829F7F8EB034F4055ADE629893A9C0926.PDF.
12. Reserve Bank of India, Press Release (2020). "Finances of Foreign Direct Investment Companies 2018-19".
13. UNCTAD/WIR, "World Investment Report", [https://unctad.org/publications-search?f\[0\]=product%3A397](https://unctad.org/publications-search?f[0]=product%3A397).